

11 Apr. 2024



डेली करंट अफेयर्स

GEO IAS

SOURCES



Date: 11 Apr. 2024

Important News Articles

1. सरकार ने बागवानी सब्सिडी वितरण के लिए CDP-SURAKSHA डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया - इंडियन एक्सप्रेस
2. पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को खारिज किया - द हिंदू
3. सुप्रीम कोर्ट ने DMRC की क्यूरेटिव पिटीशन को मंजूरी दी -
4. भारत अफ्रीका के कई देशों के लिए नए डिफेंस अटैचेस भेजेगा - द हिंदू
5. सुप्रीम कोर्ट ने 'लॉटरी किंग' के खिलाफ PMLA मुकदमे पर रोक लगाई - द हिंदू
6. जीएस !!!
7. 'गॉड पार्टिकल' की भविष्यवाणी करने वाले नोबेलिस्ट पीटर हिंग्स का निधन - न्यूयॉर्क टाइम्स
8. भारत की जलवायु नीति UNFCCC के मूलभूत सिद्धांतों से प्रेरित- इंडियन एक्सप्रेस
9. समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र हेतु मेडागास्कर में बाओबाब पेड़ों पुनर्वनीकरण प्रयास - डाउन टू अर्थ

Editorials, Gists and Explainers

10. अमेरिका-जापान-फिलीपींस त्रिपक्षीय समझौता - द प्रिंट
11. भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए फेमा अधिनियम - द हिन्दू

Quick Look

1. इन्वेसिव एलियन स्पीशीज
2. राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट
3. पैसिफ़िक रिंग ऑफ़ फायर
4. सबडक्षन
5. सुनामी

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन II

1. सरकार ने बागवानी सब्सिडी वितरण के लिए CDP-SURAKSHA डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन; इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय।

प्रीलिम्स टेकअवे

- CDP-SURAKSHA
- GVA

समाचार:

- सरकार क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए एक नया मंच लेकर आई है।
- यह बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की पहल है।
- इस प्लेटफॉर्म को CDP-SURAKSHA (CDP - सुरक्षा) के नाम से जाना जाता है।

मुख्य बिंदु

- इस कदम का उद्देश्य भारत के बागवानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है, जो कृषि सकल मूल्यवर्धन (GVA) में लगभग एक तिहाई योगदान देता है।
 - भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
- हाल के वर्षों में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन भी बढ़ा है।
- जहां वर्ष 2010-11 में यह 240.53 मिलियन टन था, वहीं वर्ष 2020-21 में यह संख्या बढ़कर 334.60 मिलियन टन हो गई।
- SURAKSHA (एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली) मूलतः एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- यह प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से e-RUPI वात्तर का उपयोग करके किसानों को उनके बैंक खाते में तुरंत सब्सिडी देने की अनुमति देगा।
- CDP-SURAKSHA में पीएम-किसान के साथ डेटाबेस एकीकरण, NIC से क्लाउड-आधारित सर्वर स्पेस, UIDAI सत्यापन, eRUPI एकीकरण, स्थानीय सरकार निर्देशिका (LGD), सामग्री प्रबंधन प्रणाली, जियोटैगिंग और जियो-फेसिंग जैसी विशेषताएं हैं।

2. पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को खारिज किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका

प्रीलिम्स टेकअवे

- ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (ऑब्जेक्शनेबल एड) एक्ट, 1954

समाचार:

- सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू योग गुरु बाबा रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दूसरे दौर की माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

मुख्य बिंदु

- शीर्ष अदालत ने नवंबर 2023 में दिए गए एक वचन का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी कि वे वर्ष 1954 अधिनियम के उल्लंघन में "इलाज" का विज्ञापन करने से बचेंगे।
- सुनवाई के दौरान अदालत ने भ्रामक विज्ञापनों पर अंखें मूद लेने के लिए उत्तराखण्ड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण पर नाराजगी जताई।

द्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (ऑब्जेक्शनेबल एड) एक्ट, 1954

- यह दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करने और उपचारों में मैजिक गुणों के दावों को प्रतिबंधित करने के लिए एक विधायी ढांचा है।
- इसमें लिखित, मौखिक और वृश्य माध्यमों सहित विभिन्न प्रकार के विज्ञापन शामिल हैं।
- अधिनियम के तहत, "दवा" शब्द का तात्पर्य मानव या पशु उपयोग के लिए इच्छित दवाओं, रोगों के निदान या उपचार के लिए पदार्थों और शरीर के कार्यों को प्रभावित करने वाले लेखों से है।
- उपभोग के लिए बनाई गई वस्तुओं के अलावा, इस अधिनियम के तहत "मैजिक रेमेडीज" की परिभाषा तावीज़, मंत्र और ताबीज तक भी फैली हुई है, जिनमें कथित तौर पर उपचार या शारीरिक कार्यों को प्रभावित करने के लिए चमत्कारी शक्तियां होती हैं।
- यह दवाओं से संबंधित विज्ञापनों के प्रकाशन पर सख्त नियम लागू करता है।
- यह उन विज्ञापनों पर रोक लगाता है जो गलत धारणाएँ देते हैं, झूठे दावे करते हैं, या अन्यथा भ्रामक हैं।
- इन प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप दोषी पाए जाने पर कारावास या जुर्माना सहित दंड हो सकता है।
- अधिनियम के तहत शब्द "विज्ञापन" सभी नोटिस, लेबल, रैपर और मौखिक घोषणाओं तक फैला हुआ है।

3. सुप्रीम कोर्ट ने DMRC की क्यूरेटिव पिटीशन को मंजूरी दी -

प्रासंगिकता: कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली - सरकार के मंत्रालय और विभाग; दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका

प्रीलिम्स टेकअवे

- पुनर्विचार याचिका

समाचार:

- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करना होगा।

क्यूरेटिव पिटीशन

- जैसा कि भारत के संविधान में उल्लिखित और वादा किया गया है, लोगों के लिए न्याय पाने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन अंतिम और अंतिम विकल्प है।
- अंतिम दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद सुधारात्मक याचिका दायर की जा सकती है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय में कोई गड़बड़ी न हो और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके।
- अदालत ने फैसला सुनाया कि यदि याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, तो सुधारात्मक याचिका पर विचार किया जा सकता है और आदेश पारित करने से पहले अदालत ने उसकी बात नहीं सुनी थी।
- यह भी स्वीकार किया जाएगा जहां एक न्यायाधीश उन तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहा जो पूर्वाग्रह की आशंका पैदा करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सुधारात्मक याचिकाएं नियमित होने के बजाय दुर्लभ होनी चाहिए और उन पर सोच-समझकर विचार किया जाना चाहिए।
- एक उपचारात्मक याचिका के साथ एक वरिष्ठ वकील द्वारा प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए, जिसमें इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त आधार बताए जाएं।

4. भारत अफ्रीका के कई देशों के लिए नए डिफेंस अटैचेस भेजेगा - द हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल हैं और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।

प्रीलिम्स टेकअवे

- मानचित्र आधारित प्रश्न
- लाल सागर

समाचार:

- सैन्य कूटनीति पर ध्यान बढ़ाने के संकेत में, भारत अफ्रीका में अपने कई मिशनों के लिए डिफेंस अटैचेस (DA) भेजने के लिए तैयार है, पहली बार यहां के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है।

मुख्य बिंदु

- यह कदम महाद्वीपों और क्षेत्रों में फैले भारतीय मिशनों में DA के एक बड़े समायोजन का हिस्सा है और इसे लागू किया जा रहा है क्योंकि भारत इंडो-पैसिफिक, लाल सागर-हिंद महासागर और यूरेशिया में गतिशील स्थितियों से निपट रहा है।
- अफ्रीका के चार देशों के अलावा पोलैंड में भारतीय दूतावास को नया DA मिलने वाला है।
- वर्तमान में चेक गणराज्य में भारतीय दूतावास में DA समर्वर्ती रूप से गारसॉ में भारतीय मिशन के लिए कार्य करता है।
- कई क्षेत्रों में DA के पद पर पुनर्समायोजन भारत की उभरती आवश्यकताओं का हिस्सा है जो रक्षा उत्पादन और सहयोग से लेकर संकट की स्थितियों से निपटने तक फैला हुआ है जो तकाल लाम्बंदी पर निर्भर है।
- इसी तरह की नई नियुक्तियां और DA के पद पर बदलाव यूनाइटेड किंगडम, रूस, फिलीपींस, आर्मेनिया में भारतीय मिशनों में भी होने की उम्मीद है।
- जबकि फिलीपींस और आर्मेनिया पहली बार भारतीय DA की मेजबानी करेंगे, रूस के मामले में, अटैचियों की संख्या कम होने की उम्मीद है।

5. सुप्रीम कोर्ट ने 'लॉटरी किंग' के खिलाफ PMLA मुकदमे पर रोक लगाई - द हिंदू

प्रासंगिकता: वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।

समाचार:

- सुप्रीम कोर्ट ने केरल की एक विशेष अदालत में 'लॉटरी किंग' के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा चलाए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी, जिसकी कंपनी अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों को एक प्रमुख दानकर्ता थी।

प्रीलिम्स टेकअवे

- | |
|----------------------------------|
| • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 |
| • ED |

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

- प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक बहु-विषयक संगठन है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार है।
- यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
- इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई, 1956 से हुई, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1947 के तहत विनियम नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में प्रवर्तन निदेशक के रूप में एक कानूनी सेवा अधिकारी की अध्यक्षता में था।
- इसकी दो शाखाएँ बम्बई और कलकत्ता में थीं।

चुनावी बॉन्ड :

- चुनावी बॉन्ड वचन पत्र की तरह धन उपकरण हैं, जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से खरीदा जा सकता है और एक राजनीतिक दल को दान दिया जा सकता है, जो बाद में इन बॉन्डों को भुना सकता है।
- बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं।
- एक व्यक्ति व्यक्तिगत होने के नाते अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकता है।

चुनावी बॉन्ड के पक्ष में तर्क

- दानदाताओं की गोपनीयता की रक्षा करने से राजनीतिक प्रतिशोध की आशंका भी काफी कम हो जायेगी
- अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत सूचना का अधिकार केवल अनुच्छेद 19(2) में सूचीबद्ध आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिसमें काले धन पर अंकुश लगाने का उद्देश्य शामिल नहीं है,

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C

- वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित होने से पहले, सभी राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के किसी भी योगदान की घोषणा करने की आवश्यकता थी।
- धारा में संशोधन, जिसने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान के लिए घोषणा करने से छूट दी थी, अदालत ने खारिज कर दिया था।

सामान्य अध्ययन III

6. 'गॉड पार्टिकल' की भविष्यवाणी करने वाले नोबेलिस्ट पीटर हिंग्स का निधन - न्यूयॉर्क टाइम्स

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और रोजमरा की जिंदगी में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।

समाचार:

- **पीटर हिंग्स**, जिन्होंने एक नए कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया और एक साल बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया, हाल ही में उनका निधन हो गया।

प्रीलिम्स टेकअवे

- गॉड पार्टिकल
- बोसॉन

गॉड पार्टिकल

- हिंग्स बोसॉन हिंग्स क्षेत्र का मूलभूत बल-वाहक कण है, जो मूलभूत कणों को उनका द्रव्यमान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
- इस क्षेत्र को पहली बार साठ के दशक के मध्य में पीटर हिंग्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिनके नाम पर इस कण का नाम रखा गया है।
- इस कण की खोज अंततः **वर्ष 2012** में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) के शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी।
 - दुनिया का सबसे शक्तिशाली कण त्वरक, यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला सीईआरएन, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- LHC ने हिंग्स क्षेत्र और उस तंत्र के अस्तित्व की पुष्टि की जो द्रव्यमान को जन्म देता है और इस प्रकार कण भौतिकी का मानक मॉडल पूरा हुआ।
- यह उन 17 प्राथमिक कणों में से एक है जो कण भौतिकी के मानक मॉडल को बनाते हैं, जो ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी निर्माण खंडों के व्यवहार के बारे में वैज्ञानिकों का सबसे अच्छा सिद्धांत है।
- हिंग्स बोसॉन उपरपरमाण्विक भौतिकी में इतनी मौलिक भूमिका निभाता है कि इसे कभी-कभी "गॉड पार्टिकल" भी कहा जाता है।
- हिंग्स बोसॉन का द्रव्यमान 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्थात् यह एक प्रोटॉन से 130 गुना अधिक विशाल है।
- यह शून्य स्पिन के साथ चार्जलेस भी है, जो कोणीय गति के बराबर एक क्वांटम यांत्रिक है।
- यह एकमात्र प्राथमिक कण है जिसका कोई चक्रण नहीं है।

7. भारत की जलवायु नीति UNFCCC के मूलभूत सिद्धांतों से प्रेरित- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे

- UNFCCC

समाचार:

- भारत की जलवायु नीति सर्वांगीण आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, घटते कार्बन बजट, UNFCCC के मूलभूत सिद्धांतों का दृढ़ पालन और जलवायु-अनुकूल जीवन शैली के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

मुख्य बिंदु

- **वर्ष 1990** का दशक भारत और दुनिया में बड़े बदलाव का समय था, जिसके कारण पर्यावरण सहित कई क्षेत्रों में नई नीतियां बनाई गईं।
- **वर्ष 1992** के रियो शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेशन (UNFCCC) और जैविक विविधता और वन सिद्धांतों पर कन्वेशन का उदय हुआ।
- रियो के बाद, भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का विभाजन धीरे-धीरे और तेजी से सामने आया।

- **UNFCCC** के लिए भारत की दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने की बहुपक्षीय प्रक्रिया में उसके विश्वास को दर्शाती है।
- भारत अपनी आर्थिक वृद्धि को **ग्रीनहाउस गैस (GHG)** उत्सर्जन से सफलतापूर्वक अलग कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005 और वर्ष 2019 के बीच इसके सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी आई है।
- यह वर्ष 2020 से पहले की अवधि में **UNFCCC** के तहत कोई बाध्यकारी शमन दायित्व नहीं होने के बावजूद है।
- पिछले 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 26 गुना से अधिक बढ़ गई है, और पवन ऊर्जा क्षमता दोगुनी से अधिक हो गई है।
- अब इसके पास पवन की चौथी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता है, और दुनिया में पांचवाँ सबसे बड़ी सौर ऊर्जा है, जिसने निर्धारित समय से नौ साल पहले नवंबर 2021 में गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है, और फिर लक्ष्य को बढ़ाकर 50% कर दिया है।
- पवन का आवास, चौबीसों घंटे बिजली, स्वच्छ पेयजल, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा और स्वच्छ रसोई गैस जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने पर भी अभूतपूर्व ध्यान दिया जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक अमिट छाप छोड़ेगा।
- भारत मानता है कि विकास और पर्यावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और सर्वांगीण समग्र विकास के लिए इन्हें एक साथ लिया जाना चाहिए।
 - भारत के सतत विकास मॉडल को विकसित देशों द्वारा प्रस्तुत आख्यानों का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों के लिए एक रैली के रूप में कार्य करना चाहिए, विज्ञान और साक्ष्य को नीति-निर्माण में सबसे आगे लाना चाहिए।

8. समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र हेतु मेडागास्कर में बाओबाब पेड़ों पुनर्वनीकरण प्रयास - डाउन टू अर्थ

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

समाचार:

- एक अभूतपूर्व संरक्षण प्रयास में, ग्लोबल सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबाब एंड मैग्रोव्स (GSPBM) ने प्रतिष्ठित बाओबाब पेड़ों को फिर से जीवंत करने के लिए एक मिशन शुरू किया है।
- वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से खतरे में पड़े इन प्राचीन दिग्गजों को अंकुर प्रत्यारोपण के माध्यम से जीवन रेखा मिल रही है।

द माइटी बाओबाब: ए सर्वाइवर इन ड्राई लैंड्स

- अफ्रीका के गर्म, शुष्क सवाना में पाया जाने वाला बाओबाब पेड़ (एडंसोनिया डिजिटाटा) अस्तित्व का समर्थक है।
- मेडागास्कर में, ये दिग्गज द्वीप के अद्वितीय वातावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- विशाल तने और गहरी जड़ों के साथ, ये विशाल जल टैंकों की तरह काम करते हैं, जो बरसात के मौसम में कठोर सूखे के दौरान उन्हें और आस-पास के पौधों को देखने के लिए पानी जमा करते हैं।
- कैट्क्टस की तरह, बाओबाब एक रसीला पौधा है, जो बारिश होने पर पानी सोख लेता है।
- ये प्रभावशाली पेड़ हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, 30 मीटर तक ऊंचे और अविश्वसनीय 50 मीटर तक पहुंच सकते हैं।
- बाओबाब पौष्टक तत्वों से भरपूर फल भी पैदा करता है, जो दुनिया में सबसे अधिक पौष्टिक में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि यह एकमात्र फल है जो प्राकृतिक रूप से शाखा पर सूख जाता है।

प्रीलिम्स टेक अवे

- बाओबाब पेड़
- अफ्रीका

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

9. अमेरिका-जापान-फिलीपींस त्रिपक्षीय समझौता - द प्रिंट

प्रासंगिकता: भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते।

समाचार:

- चीन की मुखर विदेश नीति ने हाल के वर्षों में कई मिनीपक्षीय समूहों के गठन को प्रेरित किया है।
- वर्ष 2017-2018 में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका वाले काड का पुनरुत्थान और वर्ष 2021 में AUKUS की स्थापना काफी हद तक बीजिंग की आक्रामक और जबरदस्ती नीतियों पर चिंताओं से प्रेरित थी।

लघुपक्षीय समूह: चीन के उत्थान पर एक प्रतिक्रिया

- **चीन की प्रतिक्रिया:** इंडो-पैसिफिक के देश चीन के बलपूर्वक व्यवहार से चिंतित हैं, खासकर दक्षिण चीन सागर में। इसके कारण उन्हें सुरक्षा के लिए छोटे समूहों में एकजुट होना पड़ा है।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** चीन की गतिविधि उसके पड़ोसियों को क्षेत्र की समग्र शांति और सुरक्षा के बारे में चिंतित कर रही है।
- **सामूहिक शक्ति:** देशों का मानना है कि चीन से आमने-सामने निपटने की तुलना में छोटे समूहों में मिलकर काम करना बेहतर है।
- इस तरह वे क्षेत्र को नियंत्रित करने की चीन की महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ एक मजबूत रक्षा का निर्माण कर सकते हैं।

प्रभाव:

- **मजबूत सुरक्षा:** काड (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत) जैसे समूह सुरक्षा मुद्दों पर बेहतर सहयोग, जानकारी साझा करने और चीन का मुकाबला करने के लिए सेनाओं को एक साथ प्रशिक्षण देने की अनुमति देते हैं।
- **शक्ति को संतुलित करना:** सेना में शामिल होकर, इन देशों का लक्ष्य चीन को नियंत्रण में रखना और उसे भारत-प्रशांत क्षेत्र पर हावी होने से रोकना है।
- ये यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह क्षेत्र सिर्फ चीन के ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करे।
- **गठबंधनों का स्थानांतरण:** लघुपक्षीय समूहों का उदय हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के एक-दूसरे को देखने के तरीके में बदलाव को दर्शाता है।
- ये अब अपने हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से एकजुट हो रहे हैं।
- **चीन पर दबाव:** ये समूह चीन पर अपने आक्रामक तरीकों को बदलने के लिए राजनीतिक दबाव डालते हैं।
- संयुक्त मोर्चा चीन को क्षेत्रीय स्थिरता की खातिर अधिक शांतिपूर्वक कार्य करने के लिए मना सकता है।
- **आर्थिक लाभ:** लघुपक्षीय समूह व्यापार, निवेश और विकास परियोजनाओं जैसे आर्थिक मुद्दों पर भी मिलकर काम कर सकते हैं जिससे सभी सदस्यों को लाभ होता है।

10. भारत में विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए फेमा अधिनियम - द हिन्दू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे

समाचार:

- एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा वायदा और विकल्प अनुबंधों के लिए भागीदारी मानदंड के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हालिया नीति ने इस खंड के कामकाज को बाधित कर दिया है, जिससे दैनिक कारोबार और बकाया अनुबंधों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

नए मुद्रा व्यापार नियमों से ने बाजार में हलचल

- ट्रेडिंग में गिरावट: जब से RBI के नए नियम लागू हुए हैं, एनएसई पर मुद्रा वायदा और विकल्प के दैनिक कारोबार में नाटकीय रूप से गिरावट आई है।
- इससे घरेलू दलालों और विदेशी निवेशकों दोनों को अपनी मौजूदा स्थिति को बंद करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है।
- लिकिडिटी ड्राईज़ अप : नए नियम, जो यह सीमित करते हैं कि मुद्रा डेरिवेटिव का व्यापार कौन कर सकता है, सामान्य प्रतिभागियों के एक बड़े हिस्से को बाहर रख रहा है।
- इसमें पेशेवर व्यापारी और विदेशी निवेशक शामिल हैं, जो बाजार गतिविधि का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा बनाते थे।
- भागीदारी की यह कमी बाजार की समग्र सहजता (लिकिडिटी) को खतरे में डाल रही है, जिससे रुपये के मूल्य में बेतहाशा उत्तार-चढ़ाव हो सकता है और व्यवसायों के लिए खुद को मुद्रा के उत्तार-चढ़ाव से बचाना कठिन हो सकता है।
- वोलेटिलिटी स्पिलओवर : विदेशी निवेशक जो अब भारतीय एक्सचेंजों पर व्यापार नहीं कर सकते हैं, वे अपना व्यवसाय विदेशों में रुपया NDF बाजार जैसे बाजारों में स्थानांतरित कर सकते हैं।
- इस बदलाव से रुपये की विनिमय दर में अधिक अस्थिरता हो सकती है, जिसका प्रभाव इसमें शामिल सभी लोगों पर पड़ सकता है।
- पृष्ठभूमि और चिंताएँ : अब तक, मुद्रा के उत्तार-चढ़ाव से अपने जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एक्सचेंजों पर मुद्रा डेरिवेटिव एक लोकप्रिय उपकरण रहा है, खासकर छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए।
- ये एक्सचेंज-ट्रेडेड विकल्प पारंपरिक तरीकों की तुलना में छोटे लेनदेन की अनुमति देते हैं।
- हाल के वर्षों में बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
- संतुलन अधिनियम: RBI की नई नीति का उद्देश्य सट्टा व्यापार पर नकेल कसना और यह सुनिश्चित करना है कि मुद्रा डेरिवेटिव का उपयोग केवल वैध हेजिंग उद्देश्यों के लिए किया जाए, जैसा कि मौजूदा नियमों द्वारा अनुमति है।

आगे की राह

- समाधान ढूँढ़ने में **RBI** के साथ मिलकर काम करना शामिल हो सकता है और सरकार सट्टेबाजी के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए नियमों के एक विशेष सेट से विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव को संभावित रूप से हटा सकती है, जबकि वैध हेजिंग गतिविधियों को पनपने की अनुमति भी दे सकती है।

फैक्ट फटाफट

1. इन्वेसिव एलियन स्पीशीज

- ये वे प्रजातियाँ हैं जिनका परिचय और/या उनके प्राकृतिक अतीत या वर्तमान वितरण के बाहर फैलने से जैविक विविधता को खतरा है।
- इनमें जानवर, पौधे, कवक और यहां तक कि सूक्ष्मजीव भी शामिल हैं, और सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं।
- इन प्रजातियों को प्राकृतिक या मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से परिचय की आवश्यकता है, ये देशी खाद्य संसाधनों पर जीवित रहती हैं, तेज गति से प्रजनन करती हैं और संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा में देशी प्रजातियों को पछाड़ देती हैं।
- आक्रामक प्रजातियाँ खाद्य श्रृंखला में विघटनकारी के रूप में कार्य करती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ देती हैं।
- ऐसे आवासों में जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, आक्रामक प्रजातियाँ पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी हो सकती हैं।

2. राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट

- यह नवीनतम सार्वजनिक वित्त विकास का अवलोकन प्रदान करता है, मध्यम अवधि के राजकोषीय दृष्टिकोण को अद्यतन करता है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक नीतियों के राजकोषीय निहितार्थ का आकलन करता है। इसे IMF के राजकोषीय मामलों के विभाग द्वारा वर्ष में दो बार तैयार किया जाता है।
- इसके अनुमान विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO) और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (GFSR) के लिए उपयोग किए गए समान डेटाबेस पर आधारित हैं।
- अलग-अलग देशों के लिए राजकोषीय अनुमान IMF डेस्क अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार किए गए हैं, और, WEO दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

3. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर

- इसे पैसिफिक रिम या सर्कम-पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, यह प्रशांत महासागर के किनारे का एक क्षेत्र है जो सक्रिय ज्वालामुखियों और बार-बार आने वाले भूकंपों की विशेषता है।
- यह दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखियों का घर है और दुनिया के लगभग 90% भूकंप यहाँ आते हैं।
- रिंग ऑफ फायर प्रशांत, जुआन डे फूका, कोकोस, भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई, नाज़का, अमेरिकी और फिलीपीन प्लेटों सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमाओं का पता लगाते हुए लगभग 40,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है।

4. सबडक्षन

- सबडक्षन तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेटें शिप्ट हो जाती हैं, और एक प्लेट दूसरे के नीचे धकेल दी जाती है। समुद्र तल की यह हलचल "खनिज रूपांतरण" उत्पन्न करती है
 - जिससे मैग्मा पिघलता है और जम जाता है यानी ज्वालामुखी का निर्माण होता है।
- दूसरे शब्दों में, जब एक "नीचे की ओर जाने वाली" समुद्री प्लेट को गर्म मेंटल प्लेट में धकेला जाता है, तो यह गर्म हो जाती है, अस्थिर तत्व मिश्रित हो जाते हैं और इससे मैग्मा उत्पन्न होता है।
- फिर मैग्मा ऊपर की प्लेट के माध्यम से ऊपर उठता है और सतह पर फैला जाता है

5. सुनामी

- सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाह की लहर है। इसे आमतौर पर किलर वेब्स के नाम से भी जाना जाता है।

- सुनामी सिर्फ एक लहर नहीं है, बल्कि समुद्र की लहरों की एक श्रृंखला है, जिसे पानी के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, वायुमंडलीय दबाव में तेजी से बदलाव या उल्कापिंड के कारण होने वाली तरंग ट्रेन कहा जाता है।
- हालाँकि, ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण होने वाली सुनामी कम आती हैं।
- अधिकांश सुनामी लगभग 80% प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" के भीतर आती हैं, जो भूगर्भिक रूप से सक्रिय क्षेत्र हैं जहां टेक्टोनिक बदलाव ज्वालामुखी और भूकंप को आम बनाते हैं।

6. हेपेटाइटिस

- हेपेटाइटिस संक्रामक वायरस (वायरल हेपेटाइटिस) और गैर-संक्रामक एजेंटों के कारण होता है, जिससे कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जिनमें से कुछ घातक हो सकती हैं।
- हेपेटाइटिस वायरस के पांच मुख्य प्रकार A, B, C, D और E हैं, जिनमें से प्रत्येक के संचरण के तरीके, गंभीरता, भौगोलिक वितरण और रोकथाम के तरीके अलग-अलग हैं।
- प्रकार B और C लीवर सिरोसिस (ऐसी स्थिति जिसमें लीवर जख्मी हो जाता है और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है), लीवर कैंसर और वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों का सबसे आम कारण है।

7. रोगाणुरोधी प्रतिरोध

- AMR एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है जो तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी रोगाणुरोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
- मनुष्यों, जानवरों और पौधों में रोगाणुरोधकों का दुरुपयोग और अति प्रयोग दवा प्रतिरोधी रोगजनकों के प्राथमिक चालक हैं।
- गरीबी और असमानता के कारण निम्न और मध्यम आय वाले देश AMR से असंगत रूप से प्रभावित होते हैं।
- AMR आधुनिक चिकित्सा की प्रभावकारिता को खतरे में डालता है, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और चिकित्सा प्रक्रियाएं जोखिमपूर्ण हो जाती हैं।



प्रीलिम्स ट्रैक

- Q1.** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) योजना और प्राथमिकता वाले घरों के माध्यम से 75% तक ग्रामीण और 50% शहरी आबादी NFSA द्वारा कवर की जाती है।
 - AAY परिवार सबसे निचले गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं या प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम के हकदार हैं।
 - प्राथमिकता वाले परिवारों के चयन और उनके वास्तविक सत्यापन के लिए आधार का विकास केंद्र सरकार के कर्तव्यों के दायरे में आता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

- Q2.** भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- प्रस्तावित IMEC में भारत को केवल अरब की खाड़ी से जोड़ने वाले पूर्वी गलियारों तक फैले रेलमार्ग शामिल होंगे।
- भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी हस्ताक्षरकर्ता हैं।
- भारत विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्बन बाजारों पर सहकारी कार्य समूह में शामिल होगा और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नोडल निकाय होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

- Q3.** **कथन I:** ILO के अनुसार "मुनाफा और गरीबी" शीर्षक वाली रिपोर्ट में, जबरन श्रम से कुल वार्षिक अवैध लाभ मध्य एशिया में सबसे अधिक है, इसके बाद एशिया और प्रशांत, अमेरिका का स्थान है।

कथन II: भारत का संविधान अनुच्छेद 24 के तहत जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- A. कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
- B. कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
- C. कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II कथन I की सही व्याख्या है
- D. कथन I और कथन II दोनों गलत हैं और कथन II कथन I का सही व्याख्या नहीं है

- Q4.** इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है।
- IPEF एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है और सदस्यों को उन हिस्सों पर बातचीत करने की अनुमति देता है जो वे चाहते हैं।
- भारत और प्रशांत महासागर में स्थित 13 देश इसके सदस्य हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- मनी लाइंग की रोकथाम के लिए संविधान में अलग से प्रावधान है
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) में कड़े जमानत मानक, आरोपी पर यह साबित करने की जिम्मेदारी डालते हैं कि जमानत मांगते समय उनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है।
- यदि कोई सोलह वर्ष से कम आयु का है या महिला है या बीमार या अशक्त है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश दे

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. हिंगस बोसोन हिंगस क्षेत्र का मूलभूत बलवाहक कण है, जो मूलभूत कणों को उनका द्रव्यमान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
2. इस क्षेत्र को पहली बार साठ के दशक के मध्य में पीटर हिंगस द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिनके नाम पर इस कण का नाम रखा गया है।
3. दुनिया का सबसे शक्तिशाली कण त्वरक, यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला CERN, स्विट्जरलैंड में स्थित है

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

Q7. विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अस्वास्थ्यकर हवा है और केवल 7 देश WHO के PM2.5 दिशानिर्देश को पूरा करते हैं।
2. शीर्ष पांच सबसे प्रदूषित देश एशिया और अफ्रीका में हैं।
3. भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश था, इसके 42 शहर वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में थे।
4. दस सबसे प्रदूषित शहरों में से नौ भारत में हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. केवल तीन
- D. सभी चारों

Q8. जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पार्टीयों के सम्मेलन (COP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. COP अंतरराष्ट्रीय जलवायु संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक समझौतों पर बातचीत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक वार्षिक सभा है।
2. COP28 वर्तमान में ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) को लागू करने पर केंद्रित है, जो जलवायु कार्यों को बढ़ाने के लिए 2015 पेरिस समझौते द्वारा अनिवार्य समीक्षा है।
3. मेजबान देश, संयुक्त अरब अमीरात ने COP28 के दौरान हानि और क्षति कोष का सफलतापूर्वक संचालन किया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीनों
- D. कोई नहीं

निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें

क्षेत्र	: देश
1. चुशूल	: भारत
2. गेलेफु	: यूनाइटेड किंगडम
3. ओकिनावा	: संयुक्त राज्य अमेरिका

ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- A. केवल एक युग्म
- B. केवल दो युग्म
- C. तीनों युग्म
- D. कोई नहीं

Q10. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संकेतक है जिसका उपयोग किसी देश में बेरोजगारी को मापने के लिए किया जाता है?

- A. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
- B. सकल घरेलू उत्पाद (GDP)
- C. श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)
- D. थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प A सही है

व्याख्या

- अंत्योदय अन्न योजना (AYY) योजना और प्राथमिकता वाले घरों के माध्यम से 75% तक ग्रामीण और 50% शहरी आबादी NFSA द्वारा कवर की जाती है। **अतः, कथन 1 सही है।**
- प्राथमिकता वाले घर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम भोजन के हकदार हैं।
- जबकि AYY परिवार सबसे निचले गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं या प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम के हकदार हैं। **अतः, कथन 2 सही है।**
- पूर्व योजना आयोग (अब नीति आयोग) ने वर्ष 2011-2012 के लिए NSS घरेलू उपभोग सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया था
- NSSA के तहत राज्यवार कवरेज का अनुमान लगाना।
- प्रत्येक राज्य के लिए स्थापित TPDS (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के दायरे में संभावित परिवारों की पहचान करने का कार्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पूरा किया जाना है।
- प्राथमिकता वाले परिवारों के चयन और उनके वास्तविक सत्यापन के लिए आधार का विकास राज्य सरकार के कर्तव्यों के दायरे में आता है। **इसलिए, कथन 3 गलत है।**

उत्तर : 2 विकल्प B सही है

व्याख्या

- प्रस्तावित IMEC में रेलमार्ग, शिप-टू-रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे जो दो गलियारों तक फैले होंगे, अर्थात्,
 - पूर्वी गलियारा - भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है,
 - उत्तरी गलियारा - खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है।
- IMEC कॉरिडोर में एक बिजली केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगी। **इसलिए, कथन 1 गलत है**
- भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी हस्ताक्षरकर्ता हैं **इसलिए, कथन 2 सही है**
- भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के 'स्वच्छ ऊर्जा स्तंभ' के तहत हाल ही में अनावरण किए गए चार सहकारी कार्य कार्यक्रमों में से कम से कम एक में शामिल होने का फैसला किया है।

- यह कार्बन-बाज़ार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने में से एक है।
- नई दिल्ली दो अन्य सहकारी कार्य-कार्यक्रम पहलों पर भी विचार कर रही है, जिनमें से एक स्वच्छ बिजली पर है
- दूसरा स्थायी विमानन ईंधन के उपयोग पर, लेकिन गहन विश्लेषण के बाद इसमें शामिल होने या न होने पर फैसला लिया जाएगा।
- भारत विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्बन बाजारों पर सहकारी कार्य समूह में शामिल होगा और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नोडल निकाय होगा। **इसलिए, कथन 3 गलत है**

उत्तर : 3 विकल्प D सही है

व्याख्या

- ILO के अनुसार रिपोर्ट का शीर्षक "मुनाफा और गरीबी" है।
- रिपोर्ट में कहा गया है, "जबरन श्रम से कुल वार्षिक अवैध मुनाफा यूरोप और मध्य एशिया में सबसे अधिक है, इसके बाद एशिया और प्रशांत, अमेरिका, अफ्रीका और अरब राज्यों का स्थान है।"
- भारत का संविधान अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। **इसलिए दोनों कथन गलत हैं**

उत्तर : 4 विकल्प A सही है

व्याख्या

- यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। **इसलिए, कथन 1 गलत है**

- IPEF को 2021 में एक दर्जन शुरुआती साझेदारों के साथ लॉन्च किया गया था, जो मिलकर विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% प्रतिनिधित्व करते हैं।
- IPEF एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नहीं है, लेकिन सदस्यों को उन हिस्सों पर बातचीत करने की अनुमति देता है जो वे चाहते हैं। बातचीत चार मुख्य "स्टंभों" पर होगी। **इसलिए, कथन 2 गलत है**
- आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन
- स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और बुनियादी ढांचा
- कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी
- निष्पक्ष एवं लचीला व्यापार।
- वर्तमान में, भारत और प्रशांत महासागर में स्थित 13 देश इसके सदस्य हैं, **इसलिए, कथन 3 सही है**

उत्तर : 5 विकल्प A सही है

व्याख्या

- मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है। **इसलिए कथन 1 गलत है**
- धारा 45 मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जमानत का प्रावधान करती है।
- कानून में यह प्रावधान, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) में कड़े जमानत मानक की तरह, आरोपी पर यह साबित करने की जिम्मेदारी डालता है कि जमानत मांगते समय उसके खिलाफ कोई प्रथम वृष्ट्या मामला नहीं है।
- हालाँकि, जमानत मानक में एक महत्वपूर्ण अपवाद है।
- कानून कहता है, "बशर्ते कोई व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से कम उम्र का है या महिला है या बीमार या अशक्त है, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष अदालत ऐसा निर्देश दे।"
- यह अपवाद महिलाओं और नाबालिगों के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत छूट के समान है। **अतः कथन 2 और 3 सही हैं**

उत्तर : 6 विकल्प C सही है

व्याख्या

गॉड पार्टिकल

- हिंगस बोसोन हिंगस क्षेत्र का मूलभूत बल-वाहक कण है, जो मूलभूत कणों को उनका द्रव्यमान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
- इस क्षेत्र को पहली बार साठ के दशक के मध्य में पीटर हिंगस द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिनके नाम पर इस कण का नाम रखा गया है।
- इस कण की खोज अंततः 2012 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) के शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी।
- दुनिया का सबसे शक्तिशाली कण त्वरक, यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला CERN, स्विट्जरलैंड में स्थित है। **अतः सभी कथन सही हैं**

उत्तर : 7 विकल्प D सही है

व्याख्या

- वायु गुणवत्ता तकनीक कंपनी IQAir की यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के स्तर की जांच करती है।
- वे देशों और शहरों को इस आधार पर रैंक करते हैं कि उनकी हवा कितनी साफ़ या गंदी है।

- PM2.5 (सूक्ष्म कण पदार्थ) वायु गुणवत्ता का मुख्य संकेतक है।
- डेटा 134 देशों के 30,000 से अधिक निगरानी स्टेशनों से आता है।
- वे सरकारी एजेंसियों और अपने स्वयं के सेंसर दोनों से जानकारी का उपयोग करते हैं।
- WHO वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश:
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) वायु प्रदूषण को एक प्रमुख स्वास्थ्य खतरे के रूप में देखता है।
- 2021 में, उन्होंने अपने वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों को अद्यतन किया, जिसमें छह प्रदूषकों के लिए सख्त सीमा की सिफारिश की गई।
- मुख्य निष्कर्ष (2023):
- दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अस्वास्थ्यकर हवा है। केवल 7 देश WHO की PM2.5 गाइडलाइन पर खरे उतरे।
- शीर्ष पांच सबसे प्रदूषित देश एशिया और अफ्रीका में हैं।
- भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश था, इसके 42 शहर वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में थे।
- दस सबसे प्रदूषित शहरों में से नौ भारत में हैं।
- कुल मिलाकर, रिपोर्ट वैश्विक वायु गुणवत्ता की चिंताजनक तस्वीर पेश करती है।
- **अतः, सभी कथन सही हैं।**

उत्तर : 8 विकल्प C सही है

व्याख्या

- पार्टियों का सम्मेलन (COP) वास्तव में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) द्वारा आयोजित एक वार्षिक सभा है। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर वैश्विक समझौतों पर चर्चा और बातचीत करने के लिए देशों को एक साथ लाता है। **अतः, कथन 1 सही है।**
- COP28 वर्तमान में चल रहा है, और इसका प्राथमिक फोकस ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) को लागू करना है। जीएसटी सामूहिक प्रगति का आकलन करने और वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्यों को बढ़ाने के लिए 2015 पेरिस समझौते द्वारा अनिवार्य समीक्षा है। **अतः, कथन 2 सही है।**
- मेजबान देश, संयुक्त अरब अमीरात ने COP28 के दौरान हानि और क्षति कोष का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इस कोष का उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु आपदाओं से उबरने में सहायता करना है। **अतः, कथन 3 सही है।**

उत्तर : 9 विकल्प A सही है।

व्याख्या

- द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम बड़ा संघर्ष, 1945 में 80 से अधिक दिनों तक चला।
- अमेरिकी सेना ने जापान की मुख्य भूमि के नजदीक रणनीतिक रूप से स्थित एक द्वीप ओकिनावा पर दृढ़ जापानी रक्षा से कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ी, ओकिनावा जापान में है।
- चुशुल भारत के लद्दाख के लेह ज़िले का एक गाँव है, यह दुरबुक तहसील में स्थित है, जिसे "चुशुल घाटी" के नाम से जाना जाता है।

- भूटान के राजा ने नवंबर 2023 में भारत का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने दक्षिणी भूटान के गेलोफू में माइंडफुलनेस सिटी की अपनी योजना का संकेत दिया, गेलोफू भूटान में है।

• अतः केवल एक जोड़ा सही है

उत्तर : 10 विकल्प C सही है

व्याख्या

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) बेरोजगारी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख संकेतक है। यह कामकाजी उम्र की आबादी के उस प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है जो या तो कार्यरत है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में है।





ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style. The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services



+91-9477560001 /002/005



info@geoias.com



BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna |
HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg,
Mukherjee Nagar, Delhi, 110009



www.geoias.com